



# अद्वितीय आदित्य मिशन

चंद्रयान मिशन की कामयाबी के कुछ ही दिनों बाद भारत के सूर्य मिशन की कामयाबी ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। सूर्य के अध्ययन के लिये भेजे गये आदित्य एल-1 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी, जिसके जरिये धरती के नजदीकी ग्रह सूर्य के कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अंतरिक्ष की कई हलचलों, मसलन सोलर विंड आदि का भी अध्ययन किया जायेगा। हालांकि यूरोपियन एजेंसी समेत कई देशों ने इस तरह के मिशन भेजे हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश द्वारा सीमित संसाधनों के साथ ये लक्ष्य हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। पीएसएलवी-सी 57 के जरिये अंतरिक्ष में भेजे गये आदित्य मिशन का बिलकुल सूर्य के पास जाना संभव नहीं है, लेकिन वह एक निर्धारित स्थान लैंगरेंज प्लाइट से सूर्य की क्रियाओं का अध्ययन करेगा। दरअसल, लैंगरेंज प्लाइट अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। इस स्थान पर अंतरिक्ष यान में ईंधन की सबसे कम खपत होती है और वह अधिक समय तक काम कर सकता है। सात पेलोड्स लेकर गया यह यान सूर्य की सतह पर ऊर्जा व अंतरिक्ष की अन्य हलचलों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष के मौसम पर भी इसकी नजर रहेगी। निश्चित रूप से सौर हलचलों के अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में नई जानकारी मिल सकेगी। निस्संदेह, ये नई जानकारियां मानवता के कल्याण में मददगार बनेंगी। बहरहाल, इस कामयाबी से उत्साहित इसरो को आशा है इस मिशन के जरिये हम सूर्य के बारे में नई जानकारी जुटाने में कामयाब हो सकेंगे। ये तथ्य हमारी वैज्ञानिक उत्तिम में भी सहायक बनेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि महज चार साल में बेहद कम लागत में इसरो अपने इस महत्वाकांक्षी मिशन को मूर्त रूप दे पाया है। बेहद कम बजट में बड़े मिशनों को अंजाम देने की इसरो की विशेषता का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। पिछले दिनों दुनिया की महाशक्ति रूस व अन्य बड़े देशों के मिशनों की विफलता से इतर चंद्रमा के दक्षिणी छक्के पर चंद्रयान का सफल मिशन भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा की कहानी कह रहा है। भारत की कामयाबी का एक अध्याय मंगल मिशन भी था। ऐसा करने वाला भारत एशिया का पहला देश था। इसी कड़ी में इसरो अपने महत्वाकांक्षी मानवयुक्त मिशन को अंतिम रूप देने में जुटा है। बहरहाल, रविवार को आदित्य एल-1 यान को दूसरी कक्षा में भेजकर इसरो ने बता दिया है कि मिशन सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वैसे तो लैंगरेंज पॉइंट तक पहुंचने में आदित्य एल-1 को करीब चार माह का समय लगेगा। सर्वविवित है कि हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित सूर्य की अक्षय ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब इस मिशन से होने वाले अध्ययन से पता चल सके गा कि सूर्य में होने वाले रासायनिक बदलाव हमारी धरती के जीवन व अंतरिक्ष को किस तरह प्रभावित करते हैं। धरती पर जीवन ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य के बारे में इस मिशन के जरिये मिलने वाली जानकारी निस्संदेह, मानवता के कल्याण में सहायक होगी।

## एक साथ चुनाव की मंथा कब थी?

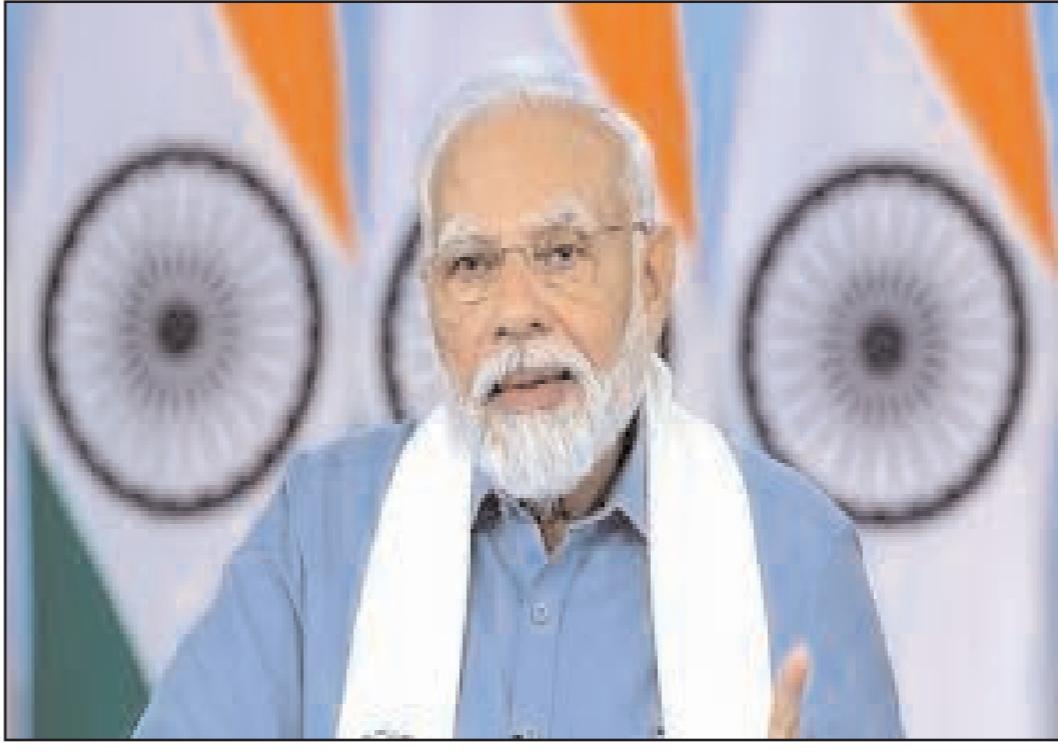
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश, एक चुनाव की बात करीब 10 साल से कह रहे हैं और चुनाव आयोग करीब 40 साल से कह रहा है। लेकिन पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वास्तविक मंशा कभी नहीं दिखी। अगर प्रधानमंत्री मोदी या चुनाव आयोग की वास्तविक मंशा होती तो अब तक कुछ सार्थक पहल फूर्हे होती। पिछले करीब 10 साल में हर साल चुनाव होते रहे और कभी यह सोचा गया कि कुछ राज्यों के चुनाव आगे पीछे करके उनको बलब किया जाए और पूरे देश में एक बार में या ज्यादा से ज्यादा दो बार में चुनाव कराए जाए। अगर ऐसा सोचा गया होता तो अब तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया होता। लेकिन अभी तक इस आइडिया का इस्तेमाल सनसनी बनाने के लिए ही किया गया है। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जा सकता है लेकिन यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है कि हर लोकसभा और हर विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा करे। इसलिए कि सीमुकाम पर गाड़ी पटरी से उत्तर सकती है, जैसे 1967 के बाद उत्तर गई थी। इसलिए ज्यादा व्यावहारिक यह है कि राज्यों के चुनाव को बलब करके दो बार में कराया जाए। पांच साल में दो बार चुनाव कराए जा सकते हैं, जैसे अमेरिका में मिड टर्म के चुनाव होते हैं। अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग चाहते तो कई साल पहले ऐसा हो चुका होता। लेकिन पिछले 10 साल में हर साल दो-दो, चार-चार महीने के अंतराल पर चुनाव होते रहे। मिसाल के तौर पर इस साल के शुरू में त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में चुनाव हुए। फिर मई में कर्नाटक के चुनाव हुए और नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव होने वाले हैं। अगले साल लोकसभा के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चुनाव हैं और साल के अंत में तीन अलग अलग महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखण्ड के चुनाव हैं। अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग एक साथ चुनाव पर सीरियस होते तो थोड़ा आगे-पीछे करके इन 16 राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते थे।

इसी तरह लोकसभा चुनाव के अगले साल यानी 2025 में जनवरी में दिल्ली में और नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। उसके अगले साल 2026 में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम में चुनाव हैं। उसके अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, मणिपुर, गोवा आदि राज्यों में चुनाव हैं। अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग गंभीरता से विचार करे तो इन तीन सालों में होने वाले चुनावों को बलब करके एक साथ 2026 में चुनाव कराया जा सकता है। इस तरह एक चक्र बन जाएगा कि लोकसभा के साथ 16 राज्यों के चुनाव और उसके दो साल बाद बाकी राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएं। यह व्यावहारिक भी है लेकिन होगा तब जब मंशा सही होगी।

एक देश-एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व में गठित आठ सदस्यीय समिति में शामिल होने से लोकसभा में कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया है कि समिति का सन्दर्भ विषय इस तरह का है कि पहले से ही इसका निष्कर्ष तय हो जाये। श्री चौधरी के कहने का मतलब है यह समिति बनाई ही गई है 'एक देश-एक चुनाव' की सिपारिश करने के लिए। बेशक श्री चौधरी के इस मत से असहमति जताई जा सकती है मगर मूल प्रश्न यह है कि हम बात किस प्रकार के चुनाव सुधारों की कर रहे हैं? भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब पूरा संविधान लिख लिया तो 25 नवम्बर, 1949 को उन्होंने इस बारे में जो भाषण दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें भारत की चुनाव प्रणाली के संरक्षक चुनाव आयोग को भारतीय लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ बताया गया था। दरअसल भारतीय लोकतन्त्र मूलतः जिन चार खम्भों पर बाबा साहेब खड़ा करके गये वे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका व चुनाव आयोग थे। इनमें से दो कार्यपालिका व विधायिका सरकार का हिस्सा थे और दो चुनाव

आयोग व न्यायपालिका सरकारी अंग न होकर स्वतन्त्र व स्वायत्तशासी थे जो सीधे संविधान से शक्ति लेकर अपने दायित्वों का निर्वाच करते चले आ रहे हैं। आजादी के बाद शुरू के तीन दशकों तक चुनाव आयोग की भूमिका बहुत पारदर्शी और शुचितापूर्ण इसके प्रकार रही कि भारत की बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था में इसके द्वारा भेदभाव किये जाने की कोई सभावना ही नहीं थी अतः समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने लोकतन्त्र में स्वतन्त्र प्रेस (मीडिया) को चौथा खम्भा कहना शुरू कर दिया और यह धीरे-धीरे स्थापित भी होता चला गया। 1969 तक चुनाव आयोग को लेकर कहीं कोई विवाद या खबर बासुधिकल ही अखबारों की सुर्खियां बन पाई। इसके साल जब पहली बार कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो लोगों को पता लगा कि कोई एस.पी. सेन वर्मा नाम का व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त भी है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के विवाद पर अपना फैसला देकर न्यायपूर्ण व्यवहार किया और लोगों की वाहवाही लूटी। मगर 1974 में दिल्ली सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसदवास्तव अमरनाथ चावला का चुनाव

# देश को संशय में डालती मोदी सरकार



ही यह इंडिया की बढ़ती एकता के जवाब में होनी चाहिये। इसे लेकर कई तरह के कथास हैं। इसमें वर्ष 2024 में होने जा रहे लोकसभा को समय से पहले करा लेने की सम्भावना से लेकर संविधान में संशोधन, चुनाव टाल देने या फिर मोदी को हमेशा के लिये पीएम बनाये जाने जैसी गुंजाइशें टटोली जा रही हैं। चीन द्वारा नया नक्शा जारी करना (जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है), मणिपुर हिंसा, गौतम अदानी को लेकर नये खुलासे, महंगाई आदि अनेक विषय हैं जिनके बारे में अनुमान व्यक्त किये जा रहे हैं कि इन मसलों पर सरकार कोई बात करना चाहती है। सही जानकारी किसी के भी पास नहीं है। फिर, हाल ही में तो संसद का सत्र हो चुका है। क्यों नहीं सरकार ने इन विषयों पर तब चर्चा कर ली? सवाल यह भी है कि क्यों लोगों या सांसदों को विषय को लेकर बताने के लिये छोड़ा जाये? क्यों सूचना के साथ ही विषय की जानकारी दे दी गई? संसद पर केवल सत्त्वर हक नहीं है, जो अन्य लोगों को इस सूचना से वर्चित रखा जाये। यह सभी दिनों का क्यों है, जबकि विशेषज्ञ एकाध दिन के ही होते हैं? दुर्भाग्यात्मक तामाशों के आयोजनों में पारंगत सरकार इसे भी इंवेंट बना रहा है।

अखिरकार विशेष सत्र कोई मजावंडी नहीं होता और न ही उसे सत्तापक्ष कोई विशेषाधिकार समझा जाये। बावजूद इसके कि सरकार को ऐसे करने का पूरा हक है। तो भी, अधिकार का प्रयोग बहुत गम्भीरता से होना चाहिये। विशेष सत्र का विषय क्या है यह किन परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है और इसे बुलाये जाना।

दे सकता है। कायदे से तो कोई व्यक्ति जिस दिन इस पद पर पहुंचता है, उसी दिन से वह दलगत राजनीति से ऊपर हो जाता है यह सब तभी सम्भव है जब किसी व्यक्ति या किसी राजनैतिक दल की ही आंखों का नहीं, किसी सरकार की आंखों का भी नहीं, बल्कि पूरे देश की आंखों का पानी मर जाये। अगर एक देश एक चुनाव की बात करें तो यह करा पाना बहुत कठिन है—प्रशासकीय और राजनैतिक दोनों कारणों से अव्यवहारिक। आजादी के बाद हुए पहले चार आम चुनावों के साथ विधानसभाओं के निर्वाचन हुए थे परन्तु तब की परिस्थितियां अलग थीं। आबादी कम थी, चुनावी हिंसा न्यूनतम थी। राजनैतिक दलों के बीच आज के जैसी वैमनस्यता भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि चुनावों का आकार व स्वरूप विशाल नहीं था। इसके बावजूद अगर सरकार एक साथ चुनाव कराना ही चाहती है तो पहले वह इसके फलदे बतलाये। यह भी बताये कि सामान्य नागरिकों, विशेषकर मरदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी में डाले बगैर ये कैसे सम्पन्न होंगे। जब मणिपुर जैसे छोटे से राज्य की हिंसा को रोकने में सरकार 5 माह में भी सफल नहीं होती और ज्यादातर राज्यों के चुनाव कई चरणों में कराने पड़ते हैं, तो इतने बड़े देश में एक दिन में कैसे चुनाव हो सकते हैं। यह जानने का हक नागरिकों का है और बतलाना सरकार का कर्तव्य।

# सिंगापुर के नए राष्ट्रपति



आज का राशि फल					
मेष	वृष	मिथुन	कर्क	सिंह	कन्या
तुला	वृश्चिक	धनु	मकर	कुम्भ	मीन

**मेघः**- पुरानी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर उत्साहित दिखेंगे। मजबूत मनोबल के साथ कुछ साहसी कायरे में हाथ डालेंगे। रोजगार में नए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जीविका क्षेत्र में नए आयाम खुलेंगे।

**बृघभः**- अच्छा होगा कि हर स्थिति का बड़ा ही नम्रतापूर्वक समना कर अच्छे व्यक्तित्व का परिचायक बनें। नये कायरे के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न तीव्र। परिवार में विवाद हो सकता है।

**मिथुनः**- पुरानी बातों को भूल कर वर्तमान के साथ समझौता करें। भौतिक आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। किसी नवी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। विरोधियों की प्रबलता रहेगी।

**कक्षः**- रोजगार के क्षेत्र में प्रयत्न सार्थक होगा। नियोजित प्रयास द्वारा कोई बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। समुचित परिश्रम पर मन के न्दित होगा।

**सिंहः**- किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। परंपरावादी व स्वाभिमानी मन व्यवहारिक जगत में तालमेल बैठाने में असमर्थ होगा। महत्वपूर्ण कायरे के प्रति आलस्य न बरतें।

**कन्या**:- समस्याओं के समाधान से उत्साह में वृद्धि होगी। सम्बन्धों में आलोचनात्मक रवैया आपकी छवि पर बुरा प्रभाव डालेगा। विभागीय परिवर्तन से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

**तुला**:- माता का भरपूर स्वेह व सहयोग प्राप्त होगा। नैतिक-अनैतिक आदि के बारे में सोचने वाला आपका मन भौतिक परिवेश तालमेल बैठाने में असमर्थ होगा। मन कुछ असमान्यताओं का शिकार हो सकता है।

**वृश्चिकः**- भविष्य सम्बन्धी कुछ चिन्ताएं मन में नीरसता लाएंगी। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुरूप चलने का प्रयत्न करें। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव।

**धनुः**- बहुत दिनों से प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन प्रसन्न होगा। व्याहारकुशलता व वाकपटुता आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पूजी है। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव।

**मकरः**- कल्पनाएं व आकांक्षाएं अपनी सार्थकता हेतु आपको उद्देलित करेंगी। वसूलपसन्द व स्वाभिमानी व्यहार लोकप्रियता दिलाने में सहायक होगी। यहां की अनुकूलता प्रगति के अच्छे अवसर प्रदान करेंगी।

**कुंभः**- किसी नए क्षेत्र में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने अंदर कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिया गया निर्णय से पश्चाताप संभव।

# चुनावों का खर्च या सरते चुनाव



के बल इसलिए अघोषित किया कि उन्होंने अपने चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च किया है तो प्रधानमन्त्री इदिरा गांधी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम - 1951 में संशोधन करके यह प्रावधान किया कि किसी भी प्रत्याशी के चुनाव पर यदि उसका कोई मित्र अथवा उसकी पार्टी जो भी खर्च करेगी वह उसके चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जायेगा तो भारत में चुनाव लगातार महंगे और खर्चोंले होते गये और चुनाव खर्च सीमा का कोई मतलब ही नहीं रहा। अतः 1974 में ही शुरू हुए जयप्रकाश नारायण के कथित सम्पूर्ण क्रान्ति आन्दोलन का मुख्य एजेंडा यह भी बना कि चुनावों को सस्ता बनाने के सरकार संवैधानिक उपाय करे जनता को चुने हुए प्रतिनिधियों वापस बुलाने का अधिकार भी जय प्रकाश नारायण ने चुनाव सुकी प्रस्तुत जरूरत बताई और जनता आह्वान किया कि वह इसकी अपुरजोर तरीके से उठाये। जेपी ने

लिए  
और  
को  
मेले।  
धारों  
ा का  
वाज  
नुनाव  
सुधारों के लिए बम्बई उच्च न्यायालय  
ने अकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री  
बी.एम. तारकूडे की अध्यक्षता में एक  
समिति बनाई जिसने आंशिक रूप से  
सरकारी खर्च से चुनाव कराये जाने के  
बारे में सिपाहियों भी दीं। जब तक ये  
सिपाहियों आयी तब तक जेर्प  
आन्दोलन में शामिल पंचमेल पार्टी

जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सत्ता पर काबिज हो गई थी। इस सरकार ने तारकुड़े समिति की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस.एल. शक्तधर के नेतृत्व में एक चुनाव सुधार आयोग का गठन कर दिया। जब तक इसकी रिपोर्ट आयी तब तक 1980 में केन्द्र में इन्दिरा जी की सरकार पुनः आ गई और शक्तधर रिपोर्ट का बहीं हश्त हुआ जो तारकुड़े समिति की रिपोर्ट का हुआ था। इसके बाद केन्द्र में कांग्रेस सरकार ने गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधारों पर किया और इसकी कुछ सिफरिसों को लागू भी किया मगर चुनावों के लगातार महंगे और खर्चीला होने से रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। असली सवाल जहां का तहां रहा कि एक नगर पालिका से लेकर विधानसभा और लोकसभा का प्रत्याशी अपने चुनाव पर बेतहाशा धन खर्च कर सकता था। जिसकी वजह से चुनाव लगातार महंगे होते गये क्योंकि इसकी जड़ में अभी तक वह कानून मौजूद है कि प्रत्याशी का निजी खर्च उसके मित्र व पार्टी द्वारा किये गये खर्च के घेरे में नहीं आयेगा। इसलिए असली समस्या तो यही है जिसे हमें हल करना है मगर हम सिर में दर्द है तो इलाज पैरों का कर रहे हैं और एक देश-एक चुनाव की बात कर रहे हैं। कहां तो बात चली थी कि चुनाव सरकारी खर्च से ही होने चाहिए और इसके लिए पृथक् से एक कोष स्थापित केन्द्र सरकार को गठित करना चाहिए जिससे गरीब से गरीब राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा हो सके और जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके मगर हम आज बात ही सरकारी खर्च को कम करने की कर रहे हैं जबकि राजनीति को बुरी तरह धनतन्त्र और धन्ना सेठों ने अपनी कृपा का पात्र बना लिया है। चुनाव सस्ते बनाने का सम्बन्ध एक बारगी ही पूरे देश में चुनाव कराने से कैसे हो सकता है जबकि विधानसभा के चुनाव में ही एक प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च करता हो और ग्राम पंचायत के चुनाव में भी लाखों रुपए खर्च किये जाते हों। लोकसभा चुनावों में तो खर्च का कोई हिसाब ही नहीं रहता यह तो अब दसियों करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच रहा है। जाहिर है कि जब इतना खर्च करने वाले प्रत्याशी मैदान में होंगे तो वे विधानसभा या लोकसभा में पहुंच कर धन सुलभ कराने वालों के हितों को ही साधेंगे। अतः चुनावों को सस्ता बनाना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।



